भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3563
दिनांक 17 दिसंबर, 2024 के लिए प्रश्न

दूध के दाम में बढ़ोतरी

3563. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से दूध का व्यवसाय किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण दूध की कम कीमत है और उत्पाद शुल्क लगातार बढ़ रहा है तथा आज एक लीटर दूध की उत्पादन लागत 27 रूपये है तथा दूध उत्पादक किसानों को एक लीटर दूध के लिए मात्र 18 से 22 रूपये ही मिलते हैं तथा शुरूआती दिनों में गाय अच्छा दूध देती है, कुछ महीनों के बाद दूध का उत्पादन कम हो जाता है तथा 6 या 7 वर्षों के बाद गाय पूरी तरह से दूध देना बंद कर देती है और ऐसी स्थिति में गौहत्या पर प्रतिबन्ध होने के कारण किसान बांझ गाय को बेच नहीं पाते हैं तथा उसकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने गन्ना और अन्य फसलों के लिए किसानों को गारंटीकृत मूल्य प्रदान करने के समान ही दूध उत्पादकों को गारंटीकृत मूल्य प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है या कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) विभाग में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, सहकारी क्षेत्र में दूध उत्पादन में 31% की वृद्धि हुई है और उसके साथ-साथ दूध प्रसंस्करण अवसंरचना में 41% की वृद्धि हुई है। यह दूध व्यवसाय की प्रगतिशील वृद्धि को दर्शाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार देश में दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री मूल्यों को विनियमित नहीं करता है। सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा उनकी उत्पादन लागत और बाजार शक्तियों के आधार पर मूल्य तय किए जाते हैं।

हालांकि, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार दूध उत्पादन और दूध प्रसंस्करण अवसंरचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूरित और संपूरित करने के लिए देश भर में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:

- (i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)
- (ii) डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDCFPO)
- (iii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)
- (iv) राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)
- (v) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)
- (vi) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)

ये योजनाएं बोवाइन पशुओं की दूध उत्पादकता में सुधार करने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद कर रही हैं। ये पहलें दूध उत्पादन की लागत को कम करने और दूध की कीमतों को स्थिर करने में मदद करने के साथ-साथ डेयरी से आय बढ़ाने में भी मदद करती हैं।